



जज एडवोकेट जनरल (JAG) भर्ती हेतु सेना का लिंग-आधारित कोटा खारिज

सेना ने JAG की भर्ती हेतु 9 में से 6 रिक्तियाँ पुरुषों के लिये आरक्षित की थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस नीति को रद्द कर दिया है।

भारत के रक्षा बलों में महिलाओं की संख्या 3,000 (2014) से बढ़कर 11,000+ (2025) हो गई है।

⌘ JAG (जज एडवोकेट जनरल) सेना की विधिक शाखा है, जो सेना अधिनियम, 1950 के तहत सैन्य विधियों के संदर्भ में सलाह देती है। JAG अधिकारी कमीशन प्राप्त कॉम्बैटेंट/लड़ाकू होते हैं जो युद्धकाल में कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में तैनात किये जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश	विवरण
सामान्य योग्यता सूची (Common Merit List)	सेना को भर्ती के लिये योग्यता-आधारित, एकल सामान्य सूची तैयार करनी होगी।
कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में समान अवसर	महिलाओं को उग्रवाद-रोधी या आतंकवाद-रोधी भूमिकाओं से बाहर रखने के संदर्भ में विधिक आधार का अभाव है, जो समानता के उल्लंघन को दर्शाता है।
संचालन क्षमता	उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रमुख उदाहरण - फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह (राफेल जेट की पायलट) - मेजर गोपिका भट्टी (आतंकवाद-प्रवण क्षेत्रों में काफिले की कमान) - कर्नल अंशु जामवाल (युद्ध क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन)

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय

वाद	वर्ष	परिणाम
सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया	2020	सेना में महिलाओं के लिये स्थायी कमीशन
कुश कालरा बनाम भारत संघ	2021	महिलाओं को NDA में प्रवेश की अनुमति

मेन्स कीवर्ड्स

⌘ “विविधता रणनीति को मजबूत करती है”: लैंगिक समावेशन से परिचालन प्रभावशीलता में सुधार होता है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, **कर्नल सोफिया कुरैशी** और **विंग कमांडर व्योमिका सिंह** ने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया जो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव का सूचक है।

⌘ “समावेश के माध्यम से शांति”: मानवीय कार्यों, शांति स्थापना तथा नागरिक अभियानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी।

⌘ “युद्ध के लिये तैयार समानता”: महिलाएँ सभी प्रकार की युद्ध-सहायक भूमिकाओं में नियुक्ति हेतु योग्य हैं।

⌘ “योग्यता लैंगिक पहचान से ऊपर है”: सशस्त्र बलों में चयन क्षमता के आधार पर न कि लैंगिक आधार पर।

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (FTSCs)

जून 2025 तक, दिल्ली में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट FTSCs ने बलात्कार और बाल यौन शोषण के केवल 43% मामलों का ही निस्तारण किया है।

FTSC योजना

⌘ परिचय:

❖ विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना (2019)।

- ❖ निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित।
- ❖ प्रत्येक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के लिये प्रतिवर्ष कम-से-कम 165 मामलों का निस्तारण करना आवश्यक है।
- ❖ योजना का विस्तार मार्च 2026 तक; 790 FTSCs बनाने का लक्ष्य।

❧ पृष्ठभूमि:

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने (जुलाई 2019) 100 से अधिक पॉक्सो मामलों (केस बैकलॉग) वाले ज़िलों के लिये विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया।
- ❖ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अनुसार विशेष न्यायालयों को अपराध का संज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी (समय पर न्याय)।

❧ प्रदर्शन:

- ❖ 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 725 FTSC कार्यरत हैं (जिनमें 392 POCSO न्यायालय शामिल हैं)।
- ❖ वर्ष 2024 में मामलों के निस्तारण की दर 96%।

चुनौतियाँ

- ❧ अपर्याप्त FTSCs: स्वीकृत 1,023 FTSC में से केवल 700 ही कार्यरत हैं; लंबित मामलों की सुनवाई पूरा करने हेतु लगभग लगभग 1,000 अतिरिक्त FTSCs की आवश्यकता है।
- ❧ गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ: इसे एक 'राजनीतिक नौटंकी' (political gimmick) माना जाता है; किसी मामले को फास्ट ट्रैक करने के लिये न्यायाधीशों की अलग से उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है इसके चलते दूसरे मामलों निस्तारण में विलंब होता है।
- ❧ पीड़ित-अनुकूल सुविधाओं का अभाव: कई FTSCs में अतिसंवेदनशील गवाह बयान केंद्रों (VWDC) तथा महिला अभियोजकों या परामर्शदाताओं का अभाव।

सुझाव

- ❧ न्यायिक सुधार: POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा महिला लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❧ पीड़ित सहायता: सभी ज़िलों में VWDC स्थापित करना; मुकदमों के दौरान सहायता के लिये बाल मनोवैज्ञानिकों की तैनाती करना।
- ❧ प्रौद्योगिकी: ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, LCD प्रोजेक्टर तथा ई-फाइलिंग प्रणालियों के साथ कोर्ट रूम का उन्नयन।
- ❧ फॉरेंसिक सुदृढ़ीकरण: DNA रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार करने तथा लंबित मामलों के निपटान हेतु फॉरेंसिक लैब्स का विस्तार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

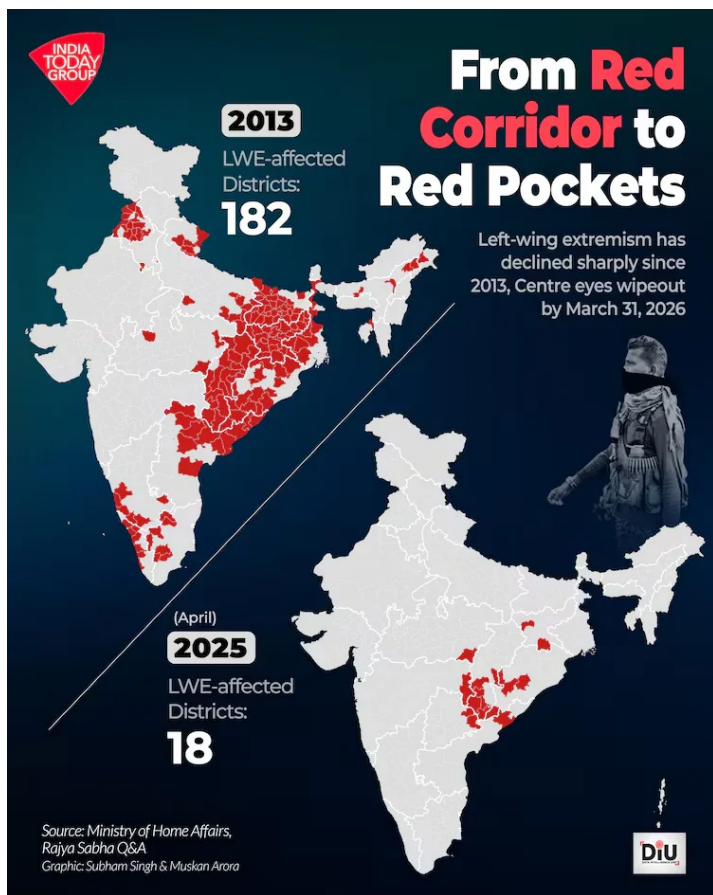
लक्षित विकास, निरंतर सुरक्षा अभियानों तथा ज़मीनी स्तर पर समर्थन में कमी के कारण रेड कॉरिडोर जो 2000 के दशक के अंत में अपने चरम पर था, अब 180 ज़िलों से घटकर मात्र 18 ज़िलों तक सीमित हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- ❧ वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटनाओं में गिरावट: 2004-14 और 2014-23 के बीच 50% से अधिक की गिरावट
- ❧ लक्ष्य: भारत का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है।
- ❧ हालिया ऑपरेशन का उदाहरण: कर्रेगुट्टालु (Karreguttalu) हिल ऑपरेशन (छत्तीसगढ़ 2025) के परिणामस्वरूप प्रमुख माओवादी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाना।

मेन्स कीवर्ड्स

- ❧ “विकास असहमति को परास्त करता है” – वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, आजीविका और कल्याण में तेज़ी।
- ❧ “संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा” – अधिकारों और स्थानीय संस्कृति के सम्मान के साथ बल का संतुलित प्रयोग।
- ❧ “उग्रवाद-विरोधी के रूप में कनेक्टिविटी” – एकीकरण के प्रवर्तक के रूप में सड़कें, दूरसंचार और डिजिटल पहुँच।
- ❧ “शिक्षा उग्रवाद का अंत करती है” – भर्ती चक्र को तोड़ने हेतु विद्यालयों की स्थापना और कौशल प्रशिक्षण।



- S** Smart Leadership
- A** Aggressive strategy
- M** Motivation and training
- A** Actionable intelligence
- D** Dashboard based KPIs
- H** Harness technology
- A** Action plan for each theatre
- N** No access to financing

8 Pillars of fighting Maoism

भारत-ओमान व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी

भारत ने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता पूरी कर ली है, जिसका उद्देश्य व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना है।

CEPA बनाम FTA

- CEPA पारंपरिक FTA की तुलना में अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी है।
- FTA मुख्य रूप से वस्तुओं पर केंद्रित है, जबकि CEPA सेवाओं, निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद तथा विवाद समाधान जैसे व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है।
- FTA की तुलना में CEPA व्यापार के नियामक पहलुओं पर अधिक गहनता से विचार करता है।



भारत-ओमान संबंध

सामरिक साझेदारी

- वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध, वर्ष 2008 में इसे सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।

बहुपक्षीय सहयोग

- ओमान GCC, अरब लीग और IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) में महत्वपूर्ण है।

व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध

- ओमान = संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद GCC में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य।
- भारत के निर्यात: हल्के तेल, चावल, मशीनरी, धातु।
- भारत के आयात: कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), उर्वरक, रसायन।

भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तंत्र

भारत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन (EO) उपग्रह तंत्र लॉन्च करेगा।

- IN-SPACe द्वारा पिक्सलस्पेस (PixxelSpace) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 5 वर्षों में 12 उपग्रहों के निर्माण के लिये चुना गया है।
- इस तंत्र या समूह में व्यापक कवरेज के लिये हाई-रिज़ॉल्यूशन, सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) और हाइपर-स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल होंगे।
- इस कदम से डेटा संप्रभुता सुनिश्चित होगी तथा विदेशी उपग्रह डेटा पर निर्भरता कम होगी।

IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाती है तथा इसरो और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

गोवा की धीरियो बुल फाइटिंग

गोवा में सांस्कृतिक और पर्यटन कारणों से सांडों की लड़ाई जिसे धीरियो या धीरी नाम से जाना जाता है, को वैध बनाने की मांग की जा रही है।

- ॐ यह पुर्तगालियों के समय से गोवा का एक पारंपरिक खेल है।
- ॐ वर्ष 1997 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

जल्लीकट्टू (तमिलनाडु में खेला जाने वाला पारंपरिक खेल जिसमें बैलों को नियंत्रित किया जाता है) को पशु क्रूरता के कारण वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा मानते हुए इसे जारी रखने की अनुमति दी।

